

# विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश  
(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 241/वि0स0/संसदीय/106(सं)/2016

लखनऊ, दिनांक 03 मार्च, 2017

## अधिसूचना

प्रकीर्ण

श्री सुरेश कुमार खन्ना, नेता, भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरहता) नियमावली, 1987 के नियम-7 के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष, विधान सभा के विचारार्थ श्री विजय बहादुर यादव, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा के विरुद्ध दिनांक 04 जुलाई, 2016 को दायर की गई याचिका पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा दिनांक 03 मार्च, 2017 को किया गया विनिश्चय एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ अधिसूचित किया जाता है :-

### अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश

श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा श्री विजय बहादुर यादव के विरुद्ध उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरहता) नियमावली, 1987 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई याचिका पर

### निर्णय

1. श्री सुरेश कुमार खन्ना, नेता, भारतीय जनता पार्टी, विधान मण्डल दल द्वारा दिनांक 04 जुलाई, 2016 को उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरहता) नियमावली, 1987 के नियम-7 के अन्तर्गत श्री विजय बहादुर यादव, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध याचिका प्रस्तुत की गई है।
2. संक्षेप में याची का यह कथन है कि विपक्षी श्री विजय बहादुर यादव, गोरखपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य के लिए वर्ष 2012 में विधान सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में विधायक चुने गये थे तथा श्री विजय बहादुर यादव तभी से उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, विधान मण्डल दल के सदस्य बन गये। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त एक राष्ट्रीय राजनैतिक दल है।
3. याची का यह कथन है कि श्री विजय बहादुर यादव सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा का नाम उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा जारी दलीय सूची में भारतीय जनता पार्टी सदस्य के रूप में दर्ज है।
4. याची के अनुसार भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रस्तर-2 (1) (ए) में यह उल्लिखित है कि यदि कोई सदस्य जिस पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुआ है उस पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है तो वह विधान सभा के सदस्य के रूप में निरह हो जायगा। याची के अनुसार भारतीय जनता पार्टी विधान मण्डल दल की बैठक दिनांक 09 जून, 2016 को बुलाई गयी थी जिसमें विधान परिषद तथा राज्य सभा के चुनाव से सम्बन्धित मतदान हेतु निर्देश दिया जाना था, किन्तु श्री विजय बहादुर यादव न बैठक में उपस्थित हुए और न ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का निर्देश प्राप्त किया।
5. याची का यह कथन कि विपक्षी द्वारा भारतीय जनता पार्टी विधान मण्डल दल के नेता व मुख्य सचेतक द्वारा घोषित निर्देशों के विपरीत अपने मताधिकार का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रत्याशी श्री शिव प्रताप के विरुद्ध मतदान किया गया। जिसे मैंने स्वयं देखा कि विपक्षी श्री विजय बहादुर यादव समाजवादी पार्टी के

घोषित राज्य सभा प्रत्याशी श्री बेनी प्रसाद वर्मा के पक्ष में प्रथम वरीयता मत देकर भारतीय जनता पार्टी की घोषित नीति-निर्देशों के विरुद्ध कार्य किया तथा उन्होंने समाजवादी पार्टी व मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की। श्री विजय बहादुर यादव का यह आचरण भारतीय जनता पार्टी के घोषित नीति के विरुद्ध है।

6. याची द्वारा यह कहा गया कि श्री विजय बहादुर यादव ने दिनांक 13 जून, 2016 को गोरखपुर में एक प्रेस कान्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी की नीतियों व कार्यक्रमों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से वक्तव्य दिया जो कि समाचार पत्रों में दिनांक 14 जून, 2016 को छपा है उनका यह आचरण भारतीय जनता पार्टी के नीति के विरुद्ध है।
7. याची द्वारा यह भी कहा गया है कि श्री विजय बहादुर यादव, विधायक गोरखपुर ग्रामीण वर्तमान समाजवादी पार्टी के सदस्य बन गये हैं तथा उनको 2017 में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश के आगामी विधान सभा चुनाव में विधान सभा क्षेत्र 323-गोरखपुर ग्रामीण से समाज वादी पार्टी ने अपना अधिकृत उम्मीदवार 17 जून, 2016 को घोषित किया है, जो समाचार पत्रों में दिनांक 18 जून, 2016 को प्रकाशित हुआ।
8. याची द्वारा यह कहा गया है कि श्री विजय बहादुर यादव को उनके द्वारा किये गये भारतीय जनता पार्टी विरोधी कृत्यों के लिए तत्काल प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी, विधान मण्डल दल से तथा भारतीय जनता पार्टी से निलम्बित कर दिया गया।
9. याची द्वारा यह भी कहा गया है कि विपक्षी श्री विजय बहादुर यादव, विधायक, गोरखपुर, ग्रामीण द्वारा लगातार भारतीय जनता पार्टी विरोधी कृत्यों तथा आचरण से स्पष्ट है कि वह भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहना चाहते। उनके उपरोक्त सभी कृत्य स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी को त्याग करके समाज वादी पार्टी में जाने तथा वहां से प्रत्याशी बनना दल परिवर्तन की परिधि में आते है।
10. अंत में श्री सुरेश कुमार खन्ना, याची द्वारा यह प्रार्थना की गयी है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा, सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के प्रस्तर-7 के अनुसार शीघ्र अति शीघ्र निर्णय लेते हुए श्री विजय बहादुर यादव, विपक्षी को भारत का संविधान की दसवीं अनुसूची सपटित अनुच्छेद, 191 (2) के अन्तर्गत विधान सभा की सदस्यता से निरर्ह (अयोग्य) घोषित किया जाय एवं उनको मिलने वाले वेतन, भत्तों सहित सभी सुविधायें भी तत्काल प्रभाव से रोकी जायं तथा इसके अतिरिक्त दल परिवर्तन करने पर नियमानुसार निर्धारित दण्ड भी दिया जाय।
11. याचिका के समस्त प्रस्तरों को उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के प्राविधानों के अन्तर्गत सत्यापित किया गया है तथा याचिका के साथ याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए एक शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। याची की ओर से संलग्नकों के रूप में विभिन्न समाचार पत्रों की प्रतियां संलग्न की गयी हैं। याचिका के साथ संलग्न अभिलिखित साक्ष्य/उपाबंधों को भी प्रमाणित किया गया है।
12. प्रस्तुत याचिका उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के अन्तर्गत प्राविधानों में वर्णित शर्तों को पूर्ण करती है। तदनुसार विपक्षी श्री विजय बहादुर यादव को उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य, (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के नियम-8 (3) के अन्तर्गत याचिका की प्रति एवं उसकी उपाबंधों सहित प्रेषित करते हुए उन्हें अपना उत्तर/टिप्पणी प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।
13. विपक्षी श्री विजय बहादुर यादव द्वारा दिनांक 29.07.2016 को अपने पत्र के माध्यम से अध्यक्ष, विधान सभा से अनुरोध किया कि उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उन्हें 02 सप्ताह का समय दिया जाय। माननीय अध्यक्ष द्वारा न्यायहित में वांछित समय प्रदान किया गया।

14. विपक्षी श्री विजय बहादुर यादव द्वारा अपने दूसरे पत्र दिनांक 16.08.2016 जो अध्यक्ष, विधान सभा को सम्बोधित है में यह अनुरोध किया कि क्षेत्र में भारी बारिश एवं बाढ़ के संकट को देखते हुए क्षेत्रीय समस्याओं के निराकरण के कारण वे अपना स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं। अतः उन्हें छः सप्ताह का समय और दे दिया जाय। माननीय अध्यक्ष द्वारा न्यायहित में वांछित समय प्रदान किया गया।
15. विपक्षी श्री विजय बहादुर यादव द्वारा अध्यक्ष, विधान सभा को सम्बोधित अपने फ़ैक्स दिनांक 19.09.2016 में यह अवगत कराया गया है कि उनकी माता जी का देहांत 15.09.2016 को हो गया है, जिसके कर्म-काण्ड में वे व्यस्त हैं। अतः उन्हें 01 माह का समय और दे दिया जाय। माननीय अध्यक्ष द्वारा न्यायहित में वांछित समय प्रदान किया गया।
16. दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को अंततः श्री विजय बहादुर यादव को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अन्तिम अवसर प्रदान किया गया। इसके पश्चात् भी प्रतिपक्षी द्वारा अपना उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तथा अंत में दिनांक 27 नवम्बर, 2016 से दिनांक 05 दिसम्बर, 2016 तक उत्तर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। श्री विजय बहादुर यादव द्वारा इसके पश्चात् भी कोई उत्तर याचिका के विरुद्ध प्रस्तुत नहीं किया गया।
17. दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 को पत्रावली पर उपलब्ध सभी अभिलेखों एवं साक्ष्यों का अवलोकन किया गया एवं चूंकि प्रतिपक्षी को पर्याप्त समय दिया जा चुका था। अतः प्रकरण निर्णय प्रदान करने हेतु नियत किया गया।
18. मैंने पत्रावली एवं सुसंगत अभिलेखों तथा साक्ष्यों का अवलोकन किया। याची द्वारा प्रतिपक्षी श्री विजय बहादुर यादव के विरुद्ध मुख्य रूप से इस आधार पर निरर्हता का अनुरोध किया गया कि उन्होंने स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता त्याग दी है तथा उनको समाजवादी पार्टी की ओर से आगामी विधान सभा निर्वाचन हेतु प्रत्याशी के रूप में घोषित किया गया है।
19. याची द्वारा याचिका के साथ प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों में सुसंगत समाचार-पत्रों की फोटो प्रतियाँ भी प्रस्तुत की गयी हैं, जिनके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस आशय का समाचार दिनांक 18 जून, 2016 को प्रकाशित किया गया था कि श्री विजय बहादुर यादव को गोरखपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी घोषित किया गया।
20. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दसवीं अनुसूची के प्रस्तर 2 (1) (क) की परिधि एवं उसके विस्तार के संदर्भ में 'किहोटोहोलोहान, रवि एस0 नायक एवं जी0 विश्वनाथन (1996) 2 एस0सी0सी0' के मामलों में पारित निर्णयों के अंतर्गत व्याख्या प्रदर्शित की है तथा यह अवधारित किया है कि सदन के किसी सदस्य द्वारा राजनीतिक दल की सदस्यता को स्वेच्छापूर्वक त्यागने का कृत्य प्रत्यक्ष (Express) अथवा विवक्षित (Implied) हो सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई विधिक व्यवस्थाओं के अनुसार सदन का कोई सदस्य विवक्षित रूप से अपने आचरण द्वारा भी राजनीतिक दल की सदस्यता का स्वेच्छा से त्याग कर सकता है।
21. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रवि एस0 नायक प्रति यूनियन ऑफ इंडिया (ए0आई0आर0 1994, एस0सी0 1558) में पारित निर्णय के अंतर्गत समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचारों को साक्ष्य के रूप में दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई याचिकाओं के निस्तारण हेतु संज्ञान में लिये जाने के विषय में मान्यता प्रदान की है जोकि निम्नवत् है:-

“As regards the reference to the news papers in the impugned order passed by the Speaker it appears that the Speaker, in his order, has only referred to the photographs as printed in the newspapers showing the appellants with Congress (I) MLAs and Dr. Barbosa, etc. when they had met the Governor with Dr. Wilfred D’Souza who had taken them to show that he had the support of 20 MLAs. The

High Court has rightly pointed out that the Speaker, in referring to the photographs was drawing an inference about a fact which had not been denied by the appellants themselves, viz., that they had met the Governor along with Dr. Wilfred D'Souza and Dr. Barbosa on December 10, 1990 in the company of congress (1) MLAs, etc. The talk between the Speaker and the Governor also refers to the same fact. In view of the absence of a denial by the appellants of the averment that they had met the Governor on December 10, 1990 accompanied by Dr. Barbosa and Dr. Wilfred D'Souza and Congress MLAs the controversy was confined to the question whether from the said conduct of the appellants an inference could be drawn that they had voluntarily given up the membership of the MGP. The reference to the newspaper reports and to the talk which Speaker had with the Governor, in the impugned order of disqualification does not, in these circumstances, introduce an infirmity which would vitiate the said order as being passed in violation of the principles of natural justice.”

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई उपर्युक्त अवधारणाओं से यह स्पष्ट है कि समाचार-पत्रों को दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत याचिकाओं के निस्तारण हेतु संज्ञान में लिया जाना सर्वथा औचित्यपूर्ण है। प्रतिपक्षी की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य अथवा आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे कि उपर्युक्त समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचारों का कोई खण्डन किया गया हो, अतः याची द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्य एवं तर्क विधिक रूप से मान्य है।

22. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह राणा प्रति श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, (ए0आई0आर0/एस0सी0 1305, 2007) में यह स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि निरर्हता उसी दिन से लागू एवं प्रभावी मानी जायेगी जिस दिन से सम्बन्धित सदस्य द्वारा स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल का त्याग किया गया हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय के निम्नलिखित अंश सुसंगत हैं।

“As we see it, the act of disqualification occurs on a member voluntarily giving up his membership of a political party or at the point of defiance of the whip issued to him. Therefore, the act that constitutes disqualification in terms of paragraph 2 of the Tenth Schedule is the act of giving up or defiance of the whip. The fact that a decision in that regard may be taken in the case of voluntarily giving up by the Speaker at a subsequent point of time cannot and does not postpone the incurring of disqualification by the act of the legislator. Similarly, The fact that the party could condone the defiance of a whip within 15 days or that the Speaker takes the decision only thereafter in those cases, cannot also pitch the time of disqualification as anything other than the point at which the whip is defied. Therefore in the background of the object sought to be achieved by the Fifty-Second Amendment of the Constitution and on a true understanding of paragraph 2 of the Tenth Schedule, with reference to the other paragraphs of the

Tenth Schedule, the position that emerges is that the Speaker has to decide the question of disqualification with reference to the date on which the member voluntarily gives up his membership or defies the whip. It is really a decision ex post facto. The fact that in terms of paragraph 6 a decision on the question has to be taken by the Speaker or the Chairman, cannot lead to a conclusion that the question has to be determined only with reference to the date of the decision of the Speaker. An interpretation of that nature would leave the disqualification to an indeterminate point of time and to the whims of the decision making authority. The same would defeat the very object of inacting the law. Such an interpretation should be avoided to the extent possible. We are, therefore, of the view that the contention that only on a decision of the Speaker that the disqualification is incurred, cannot be accepted.”

23. भारत का संविधान के 52वें संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को समाहित किया गया था जिसका कि मुख्य रूप से यह उद्देश्य था कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार जिस दल से प्रत्याशी निर्वाचित होता है उसके अतिरिक्त अन्य दल के प्रति यदि वह आस्था अथवा प्रतिबद्धता प्रकट करता है तो वह उपयुक्त नहीं है। जैसाकि रवि एस0 नायक के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया जा चुका है। निरर्हता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आचरण के अवधारित पर आधारित हो सकता है, प्रस्तुत प्रकरण में चूंकि श्री विजय बहादुर यादव को समाजवादी पार्टी द्वारा आगामी विधान सभा चुनाव या निर्वाचन के लिए प्रत्याशी घोषित किया जा चुका है। अतः श्री विजय बहादुर यादव को 10वीं अनुसूची के अन्तर्गत सुसंगत प्राविधानों के अनुसार निरर्हता से ग्रसित माना जायेगा।
24. उपर्युक्त प्राविधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यदि कोई सदस्य जिस दल से निर्वाचित हुआ है उसके अतिरिक्त किसी दल में सम्मिलित होता है तो वह निरर्हता से ग्रस्त होगा, चूंकि श्री विजय बहादुर यादव को समाजवादी पार्टी द्वारा अपना अधिकृत प्रत्याशी आगामी विधान सभा हेतु घोषित किया जा चुका है। अतः यह स्पष्ट है कि श्री विजय बहादुर यादव समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हो गये हैं। वर्णित स्थिति में श्री विजय बहादुर यादव के मामले में 10वीं अनुसूची के प्रस्तर-2 (1) के प्राविधान आकर्षित होते हैं तदनुसार वह उसी दिनांक से निरर्ह माने जायेंगे, जिस दिनांक से उनको समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी आगामी विधान सभा चुनाव के लिए घोषित किया गया है।
25. प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि साक्ष्य के रूप में याची द्वारा विभिन्न समाचार-पत्रों की प्रतियाँ प्रस्तुत की गयी हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत का संविधान की 10वीं अनुसूची के पैरा-2 दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता-(1) पैरा-4 और पैरा-5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सदन का कोई सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, सदन का सदस्य होने के लिए उस दशा में निरर्हरित होगा जिसमें-

(क) उसने ऐसे राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता से स्वेच्छा से छोड़ दी है या

(ख)-----

चूंकि श्री विजय बहादुर यादव को समाजवादी पार्टी की ओर से आगामी विधान सभा में प्रत्याशी के रूप में घोषित किया जा चुका है, अतः यह माना जायेगा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वर्णित स्थिति में यह स्पष्ट है कि श्री विजय बहादुर यादव द्वारा स्वेच्छा से अपने मूल राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को त्याग दिया है, अतः श्री यादव के सम्बन्ध में 'भारत का संविधान' की 10वीं अनुसूची में के प्रस्तर-(2)(1)(क) में वर्णित प्रावधान आकर्षित होते हैं एवं इसके फलस्वरूप श्री यादव 16वीं विधान सभा की सदस्यता से उस दिनांक से निरर्हित माने जायेंगे जिस दिनांक से वह समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुए।

26. याची की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जी0 विश्वनाथन प्रति माननीय अध्यक्ष, तमिलनाडु विधान सभा एवं अन्य में पारित निर्णय पर अत्यधिक बल देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि किसी सदस्य का निष्कासन मूल राजनीतिक दल से हो भी जाता है तो उसके विषय में निरर्हता आकर्षित हो सकती है यदि वह स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता को त्याग करने का आचरण करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त विधि व्यवस्था में यह अवधारित किया गया है कि मूल राजनीतिक दल से पृथक होने अथवा उससे निष्कासन के पश्चात् भी 10वीं अनुसूची के प्रयोजन हेतु यह माना जायेगा कि ऐसे सदस्य मूल राजनीतिक दल का ही सदस्य है।

प्रस्तुत प्रकरण में चूंकि श्री विजय बहादुर यादव को निष्कासित किये जाने के विषय में तथ्य अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः तकनीकी रूप से जी0 विश्वनाथन के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय आकर्षित नहीं होता है। प्रस्तुत प्रकरण में याचिका में वर्णित तथ्यों के अनुसार श्री विजय बहादुर यादव को अपने मूल राजनीतिक दल से निलम्बित किया गया है न कि निष्कासित किया गया है। चूंकि श्री विजय बहादुर यादव को मूल राजनीतिक दल से पूर्ण रूप से पृथक अथवा निष्कासित नहीं किया गया है। अतः प्रस्तुत मामले में जी0 विश्वनाथन का निर्णय लागू नहीं माना जायेगा, परन्तु इस सम्बन्ध में यह भी दृष्टव्य है कि जी0 विश्वनाथन के निर्णय में निहित मन्तव्यों के अनुसार निलम्बन के पश्चात् भी 10वीं अनुसूची के उद्देश्यों के हेतु यह माना जायेगा कि श्री विजय बहादुर यादव अपने मूल राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी से ही सम्बद्ध हैं। उस सीमा तक जी0 विश्वनाथन के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित की गयी विधि व्यवस्थाओं का अवलम्बन प्रस्तुत प्रकरण में लिया जा सकता है।

27. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों, विधिक प्राविधानों एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गयी विधि व्यवस्थाओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि श्री विजय बहादुर यादव दिनांक 17 जून, 2016 से निरर्ह माने जायेंगे, क्योंकि उसी दिनांक से उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की तथा उनको समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया। इस आशय का समाचार दिनांक 18 जून, 2016 को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया, जिससे कि यह स्पष्ट है कि श्री विजय बहादुर यादव द्वारा अपने मूल राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से त्याग दी गयी। वर्णित स्थिति में मेरा यह सुविचारित समाधान है कि श्री विजय बहादुर यादव के सम्बन्ध में भारत का संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रस्तर-2 के प्राविधान आकर्षित होते हैं जिसके फलस्वरूप श्री विजय बहादुर यादव दिनांक 17 जून, 2016 को निरर्हता से ग्रसित हो गये।

## आदेश

श्री सुरेश कुमार खन्ना नेता, भारतीय जनता पार्टी, विधान मण्डल दल द्वारा प्रस्तुत की गयी याचिका को स्वीकार किया जाता है। श्री विजय बहादुर यादव, सदस्य, उत्तर प्रदेश, विधान सभा क्षेत्र गोरखपुर ग्रामीण, विधान सभा क्षेत्र जिला गोरखपुर को भारत का संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रस्तर-2 (1) (क) के अन्तर्गत दिनांक 17 जून, 2016 से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता से निरह घेषित किया जाता है।

दिनांक 03 मार्च, 2017

**माता प्रसाद पाण्डेय,**  
अध्यक्ष,  
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,  
**प्रदीप कुमार दुबे,**  
प्रमुख सचिव,  
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

-----

संख्या : 241(2)/वि0स0/संसदीय/106(सं)/2016, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित :-

- 1-महामहिम राज्यपाल के प्रमुख सचिव को महामहिम राज्यपाल की सूचनार्थ,
- 2-मा0 मुख्य मंत्री के प्रमुख सचिव को मा0 मुख्य मंत्री की सूचनार्थ,
- 3-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
- 4-श्री सुरेश कुमार खन्ना, नेता, भारतीय जनता पार्टी, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
- 5-समस्त मा0 सदस्यगण, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
- 6-श्री विजय बहादुर यादव, ग्राम-भरवलिया बुजुर्ग, पो0-न्यू शिवपुरी कालोनी, जनपद-गोरखपुर,
- 7-सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली,
- 8-मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 9-प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद्, उत्तर प्रदेश,
- 10-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य अनुभाग-1,
- 11-प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
- 12-सचिव, विधि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली,
- 13-सरकारी सचिवालय के समस्त विभाग,
- 14-निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क अनुभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 15-महासचिव, राज्य सभा, नई दिल्ली,
- 16-महासचिव, लोक सभा, संसद भवन, नई दिल्ली,
- 17-प्रमुख सचिव/सचिव, समस्त राज्य विधान सभा/परिषद्,
- 18-जिलाधिकारी, गोरखपुर,
- 19-विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग।

**अशोक कुमार चौबे,**  
संयुक्त सचिव।